इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष 40/रुपये
(आईएसओ 9001 : 2008 प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : 5 अंक सं. : 11 जून, 2013

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मुख्य घटनाएं ---------- 1
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------1
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- 2
विनियामकों के कथन ----------4
बीमा /अर्थव्यवस्था----------4
उत्पाद एवं गठजोड़----------5
नयी नियुक्तियां----------5
ग्रामीण बैंकिंग / विदेशी मुद्रा ----------5
वित्तीय समावेशन ---------- 6
सूक्ष्म वित्त /अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारीं / शब्दावली---------- 7
संस्थान की गतिविधियां ----------7
संस्थान समाचार----------7

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएं

बैंक ई-नालामियों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत

एक ई-प्रोक्योरमेंट और ई-सोर्सिंग समाधान प्रदानकर्ता,, सी1 इंडिया ने बैंकों को उनकी दबावग्रस्त आस्तियों की नीलामी करने में समर्थ बनाने के लिए www.bankeauctions.com नामक ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की है। इस पोर्टल की सहायता से बैंक कुछेक सरल उपायों में अनुवृत्त सृजित और प्रकाशित करने तथा सम्पूर्ण प्रक्रिया पर ऑनलाइन निगरानी रखने में समर्थ होंगे। उक्त प्रणाली किसी अनुवृत्त के सृजन से लेकर नीलामी के संचालन तक की पूरी नीलामी प्रक्रिया को स्वचालित बना देती है। यह ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) और वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निमाण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेयसी) से सम्बन्धित अनुवृत्तो ं, दोनों ही की सहायता करती है। चूंकि इस सॉफ्टवेयर की शुरुआत हाल ही में हुई है, उक्त पोर्टल से लगभग 3.000 अनुवृत्तों के माध्यम से 2,800 करोड़ रुपये की नीलामी सम्पन्न हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश बैंकों ने ई-नालामी सेवाओं का उपयोग करने हेतु इस पोर्टल के साथ करार किया है। पिछले वर्ष वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ऋण वसूली न्यायाधिकरण / सरफेयसी कानूनों के तहत उलझी उनकी दबावग्रस्त आस्तियों की ई-नीलामी की शुरुआत करने हेतु कहा था।

आवास वित्त कम्पनियों के विनियामक का कार्य भारतीय रिज़र्व बैंक करेगा

भारतीय आवास बैंक (NHB) के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री आर.वी. वर्मा ने कहा है कि राष्ट्रीय आवास बैंक (संशोधन) विधेयक को संसद का अनुमोदन मिल जाने पर आवास वित्त कम्पनियों (HFCs) के पंजीकरण और विनियमन से सम्बन्धित कार्य राष्ट्रीय आवास बैंक से भारतीय रिज़र्व बैंक को अंतरित हो जाएंगे। इसके फलस्वरूप आवास ऋणों का एकमात्र विनियामक रह जाएगा। वर्तमान में बैंकों द्वारा दिए गए आवास ऋणों के लिए विनियामक भारतीय रिज़र्व बैंक है और तथा आवास वित्त

कम्पनियों द्वारा प्रदान किए गए इसी प्रकार के ऋणों का विनियमन राष्ट्रीय आवास बैंक करता है। बैंकों और आवास वित्त कम्पनियों के लिए विवेकसम्मत मानदंडों, जोखिम-भारों, प्रावधानीकरण तथा उसके साथ ही साथ अनर्जक आस्तियों के निर्धारण सहित अधिकांश नियम एक जैसे ही हैं, अलबत्ता,

(आवास वित्त कम्पनियों के लिए 12% की तुलना में 9% के) कमतर पूंजी पर्याप्तता अनुपात के कारण बैंक लाभजनक स्थिति में हैं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

भारतीय रिज़र्व बैंक का बैंकों को निर्देश : नोट स्टैपल न करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को नोटों के पैकेटों को स्टेपल न करने का निदेश दिया है। इसके बजाय उन्हें नोटों के पैकेटों को कागज़ की पट्टियों से सुरक्षित करना चाहिए तथा नोटों को पुन: जारी करने योग्य एवं जारी न करने योग्य नोटों के रूप में छांट लेना चाहिए और जनता को केवल स्वच्छ करेंसी नोट जारी करना चाहिए। उसने बैंकों से बैंक नोटों के वाटरमार्क पटल पर किसी भी प्रकार की लिखावट के कार्य को बंद कर देने के लिए भी कहा है।

पूंजी निर्गमों के विवरण प्रकट करें

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को जारी किए गए सभी पूंजी लिखतों के विवरण उनके तुलनपत्र में प्रकट करने का निदेश दिया है। बासेल -III पूंजीगत सुधारों की पुष्टि करने के लिए जारी नये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे तथा ऋणदाताओं को उनके सितम्बर के अंत वाले तुलनपत्रों में इन विवरणों की रिपोर्ट देनी होगी। इससे विनियामक पूंजी की पारदर्शिता में सुधार आने और बाज़ार अनुशासन बढ़ाने में मदद मिलने की आशा है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा सोने के आयात को सीमित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों द्वारा स्वर्णाभूषणों के निर्यात की वास्तविक जरूरतें पूरी करने के लिए केवल परेषण के आधार पर ही बुलियन के आयात को सीमित करने के अपने प्रस्ताव को अधिसूचित कर दिया है। यह घरेलू उपयोग के लिए सोने की मांग को नियंत्रित करने के लिए प्रस्तावित किया गया है और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सोने की मांग के तीन स्रोत हैं - उपभोग, निवेश और सट्टेबाजी । कीमतों के घट जाने पर उपभोग की मांग बढ़ सकती है, किन्तु निवेश और सटोरिया मांग में कमी आ सकती है। चालू खाते के घाटे के प्रबन्धन, वित्तीय स्थिरता के प्रबन्धन तथा व्यापक उपभोक्ता संरक्षण को लेकर भारतीय रिज़र्व बैंक चिंतित है। इस नीति में शामिल एक उपाय है जब तक कि वह निर्यात के उद्देश्य से न हो बैंकों को परेषण के आधार पर सोने का आयात करने से रोकना।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

4

सेक्टर-वार ऋण वृद्धि घट कर 8% हुई

ऋण के सेक्टर-वार अभिनियोजन से सम्बन्धित भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (आवास, कृषि और कमजोर वर्गों को प्रदत्त लघु आकार वाले ऋणों सहित) को बैंकों के ऋणों में 22 मार्च, 2013 के दिन 15,45,448 करोड़ रुपये के बकाये की तुलना में केवल 8.6% की वृद्धि हुई। यह पिछले वित्त वर्ष की 12.1% की वृद्धि के मुकाबले बहुत कम है। सेक्टर में भी आवास ऋण गतिहीन रहे तथा कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों को ऋणों में 8.1% की सर्वाधिक मंद वृद्धि दर्ज हुई। वर्ष 2011-12 में संकुचन आने के बाद 2012-13 में 3 % की दर से पुनरुत्थान परिलक्षित हुआ। भारतीय रिज़र्व बैंक वित्तीय समावेशन में तेजी ला रहा है तथा बैंकों से भीतरी प्रदेशों में शाखाएं खोलने अथवा वहां तक कारबार संपर्कियों के माध्यम से पहुंचने के लिए कहा है। बैंकों से उनके शाखा नेटवर्क का 25% बैंक-रहित क्षेत्रों में रखने हेतु भी कहा गया है।

बैंक स्वर्ण ईटीएफ पर उधार नहीं दे सकते

सोने के आयात को नियंत्रित करने हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को शेयर बाज़ार में खरीदी-बेची जाने वाली स्वर्ण निधियों (ETFs) और स्वर्ण पारस्परिक निधियों पर ऋण देने से रोक दिया है। उसने गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों को भी किसी भी रूप में सोने पर ऋण देने से रोक दिया है। वर्ष 2013-14 (अप्रैल-मार्च) के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह कहा गया था कि किसी भी रूप में सोने अर्थात् अपरिष्कृत सोना, स्वर्ण बुलियन, स्वर्णाभूषण, सोने के सिक्कों, स्वर्ण ईटीएफ की यूनिटों और स्वर्ण पारस्परिक निधियों की यूनिटों की खरीद के लिए बैंकों द्वारा किसी प्रकार का अग्रिम नहीं मंजूर किया जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने विशिष्ट रूप से ढाले गए सोने के सिक्कों पर बैंक ऋणों को भी 50 ग्राम / ग्राहक तक सीमित कर दिया है। इससे पीली धातु पर उधार देने में बुलियन और आभूषण के बीच मौजूद अंतर के भी रेखांकित हो जाने की आशा है। वर्तमान में बैंक स्वर्णाभूषणों तथा बैंकों द्वारा बेचे जाने वाले विशिष्ट रूप से ढाले गए सोने के सिक्कों पर ऋण मंजूर कर सकते हैं, किन्तु किसी भी रूप में सोने की खरीद के लिए कोई अग्रिम नहीं मंजूर कर सकते।

अप्रैल में कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष ने 5,848 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकार किये

कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष द्वारा मार्च में 12,655 करोड़ रुपये की तुलना में अप्रैल में पुनर्व्यवस्था के लिए 5,848 करोड़ रुपये के ऋण स्वीकार किए गए हैं। पिछले वर्ष अप्रैल-जून की अवधि में कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष ने 17,957 करोड़ रुपये के 17 मामले स्वीकार किए थे। इसके अतिरिक्त मार्च,

2013 में 22,692 करोड़ रुपये के 18 मामलों के मुकाबले कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था कक्ष को 4,747 करोड़ रुपये के पांच मामले भेजे गए।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उधारकर्ताओं को एसएमएस चेतावनी भेजेंगे

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उधारकर्ताओं को ऋण चुकौती तिथियों के बारे में नियमित एसएमएस और फोन चेतावनियां तथा उनके ऋणों के अनर्जक आस्ति हो जाने के सम्बन्ध में चेतावनियां मिलनी शुरू हो सकती हैं। यह कार्रवाई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को वित्त मंत्रालय के उस निदेश के अनुसरण में की जाएगी जिसमें उनसे सक्रिय रहने और उधारकर्ताओं के नकदी प्रवाह की स्थिति का निरंतर आधार पर मूल्यांकन करते हुए और 90 दिनों की निर्धारित अवधि समाप्त होने तक प्रतीक्षा करने तथा खाते को अनर्जक आस्ति मानने की बजाय उन्हें देय तिथियों के बारे में नियमित अनुस्मारक भेजते हुए ऋणों की समय पर वसूली हेतु गहन कार्रवाई करनी है।

मुद्रस्फीति में कमी के कारण सरकारी बॉण्ड के प्रतिफल में कमी

अप्रेल में सुर्खियों में आई मुद्रास्फीति के घट कर 4.89% हो जाने के परिणामस्वरूप न्यूनतम 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूति (G-secs) का प्रतिफल दो दिनों में उसकी कीमत में 85 पैसे के उछाल के बावजूद 13 आधार अंकों की कमी के साथ 7.45% रह गया। सरकारी प्रतिभूतियों के प्रतिफल और कीमतें विपरीत क्रम में सह-सम्बन्धित होते हैं। मुद्रास्फीति की अद्यतन स्थिति, जो भारतीय रिज़र्व बैंक के 5% के मध्यकालिक स्तर सहूलियत वाले स्तर की तुलना में अनुकूल है, से बाज़ार के सहभागियों में इस आशा का संचार हुआ है कि शीर्ष बैंक जून माह की अपनी आगामी समीक्षा में पुनर्खरीद (Repo) दर में 25 आधार अंकों की कमी करेगा।

बैंक निधियों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण के सम्बन्ध में और जांच की तैयारी में

खातों के बीच इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण और चालू खाते खोलना शीघ्र ही और कठिन हो सकता है। धोखाधड़ियों को नियंत्रित रखने के एक अभियान में बैंक चालू खातों के परिचालन के सम्बन्ध में सुरक्षात्मक उपायों का नया सेट लागू करने की तैयारी में हैं। यहां तक कि बचत बैंक खाता धारकों को भी इस कठिनाई से गुजरना पड़ सकता है, क्योंकि बैंक इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (EFT) या तत्काल सकल भुगतान (RTGS) चैनल पर अधिक जांच लागू करने वाले हैं।

उधार लेना मंहगा होगा

गतिशील ऋणगत हानि प्रावधानों को संशोधित करने और कम्पनियों के अप्रतिरक्षित विदेशी ऋण जोखिमों (Ezposures) के लिए जोखिम-भारों एवं प्रावधानों को बढ़ाने की भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्रवाई से बैंकों की लाभप्रदता और पूंजीकरण प्रभावित हो सकते हैं। गतिशील प्रावधानीकरण बैंकों

को जब उनके लाभ बढ़ रहे हों उस समय ऋणगत हानि के लिए प्रावधान करने की सुविधा प्रदान करते हैं, ताकि आर्थिक मंदी के दौरान इन प्रावधानों से आहरित किया जा सके। निहित सिद्धांत यह है कि दीर्घ-काल या चक्रों के दौरान अपेक्षित हानियों के अनुरूप रकमें अलग रख दी जानी चाहिए। बैंक व्यवसाय चक्र के प्रति प्रवण होते हैं। अच्छे समय में ऋण की मांग में वृद्धि हो जाती है और बैंक ऋण मानकों में कुछ गिरावट के परिणामस्वरूप आक्रामक हो उठते हैं। उधारकर्ता ऋणों की चुकौती

समय से करते हैं। ऋणगत हानि की दरें दीर्घकालिक औसत से कम रहती हैं तथा ऋणगत हानि हेतु प्रावधान की आवश्यकता कम हाती है। उत्कर्ष वाली अवधि के दौरान ये प्रावधान सामान्य रूप से अल्पनिधिक रहते हैं। जब व्यवसाय चक्र बदलता है और आर्थिक स्थितियों में गिरावट आती है, तो उधारकर्ताओं की ऋण गुणवत्ता घट जाती है। चूकों (ब्याज और मूलधन के भुगतानों की चुकौती) में वृद्धि हो जाती है। कुछ ऋण अनर्जक आस्तियां बन जाते हैं। बैंकों के लाभ में कमी आ जाती है, किन्तु उन्हें अशोध्य ऋणों के लिए अपेक्षाकृत अधिक ऋणगत हानि के प्रावधान करने पड़ते हैं।

बैंक छात्र उधारकर्ताओं को पैन (PAN) प्रस्तुत करने हेतु उकसा रहे हैं

उच्चतर शिक्षा पूरी कर लेने के बाद छात्रों को गायब हो जाने से रोकने के लिए बैंक ऋण लेते समय उन्हें स्थायी खाता संख्या (PAN) के लिए आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित कर रहे हैं। स्थायी खाता संख्या ऋण की चुकौतौ से सम्बन्धित चूककर्ताओं का पता लगाने में बैंकों की सहायता करेगी। यद्यपि छात्र उधारकर्ताओं के लिए स्थायी खाता संख्या (PAN) अनिवार्य नहीं है, बैंकरों को ऐसा लगता है कि उन्हें उनका पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले इसे प्राप्त कर लेना चाहिए तथा बैंक को सूचित करना चाहिए। 22 फरवरी, 2013 के दिन मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पास कुल मिला कर (24 फरवरी, 2012 के दिन 50,000 करोड़ रुपये के मुकाबले) 55, 100 करोड़ रुपये का शिक्षा ऋण संविभाग मौजूद था।

निर्यात ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार में

भारतीय रिज़र्व बैंक की एक आंतरिक समिति ने यह सिफारिश की है कि निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए निर्यात ऋण को सभी बैंकों के मामले में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए। वर्तमान में, केवल विदेशी बैंकों के लिए यह आवश्यक है कि वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के तहत अपने कुल ऋणों का 12% निर्यात कम्पनियों को संवितरित करें। अन्य सभी बैंकों के लिए निर्यात वित्त 40% के प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र अधिदेश के बाहर है।

बीमा दलाली व्यवसाय करने वाले बैंकों के लिए नये दिशानिर्देश

बीमा दलाल बनने के इच्छुक बैंकों को उस दलाली शाखा को अलग करना पड़ सकता है जो एक स्वतंत्र रूप से जिम्मेदार इकाई होगी। बीमा दलाली के सम्बन्ध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि बैंक की दलाली इकाई में अपेक्षित अर्हताओं, अनिवार्य

सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण तथा परीक्षा निकाय द्वारा अपेक्षित परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। शेष कर्मचारियों को सम्बन्धित बीमा संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और दलाली संघ एवं बीमा क्षेत्र के अन्य हितधारकों द्वारा आयोजित निरंतर स्वरूप वाले शैक्षणिक कार्यक्रमों में सहभागिता करने के साथ ही आचार संहिता के एक खण्ड में विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण सम्बन्धी अपेक्षाओं को पूरा करने वाला होना चाहिए। दलालों के रूप में कार्य करने वाले बैंक शाखाओं के

संपूर्ण नेटवर्क के उपयोग में समर्थ बनाएंगे और बीमे की पैठ बढ़ाएंगे एवं उसके साथ ही सेवाएं प्रदान करने में प्रतियोगिता को भी बढ़ावा देंगे।

भारतीय रिज़र्व बैंक के पैनल ने बिल भुगतानों के लिए केन्द्रीकृत प्रणाली प्रस्तावित की

भारतीय रिर्ज़ बैंक द्वारा गठित एक समिति ने समस्त बिल भुगतानों के प्रबन्धन के लिए ग्राहक सेवा केन्द्रों के माध्यम से बिल-निर्माताओं को समाहर्ताओं एवं ग्राहको के माध्यम से जोड़ते हुए केन्द्रीकृत मूलभूत सुविधा के रूप में कार्य करने हेतु एक भारतीय बिल भुगतान प्रणाली (IBPS) का गठन प्रस्तावित किया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री जी. पद्मनाभन की अध्यक्षता वाली उक्त समिति का गठन भारत में गिरो-आधरित भुगतान प्रणाली कार्यान्वित किए जाने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने हेतु किया गया था। गिरो भुगतान अदाकर्ता द्वारा आरंभ किया जाने वाला एक ऋण वर्धक लेनदेन है तथा इसमें तीन बैंकों - वसूलीकर्ता बैंक, अदाकर्ता बैंक और आदाता बैंक की उपस्थिति आवश्यक हो सकती है । ग्राहक प्रस्तावित गिरो प्रणाली के तहत बैंकों / बैंकेतर संस्था के माध्यम से किसी भी भुगतान चैनल का उपयोग कर सकता है। समिति आवश्यक सेवाओं की देय राशियों, बीमा प्रीमियमों, उपयोगिता भुगतानों, करों, विश्वविद्यालय शुल्कों, परीक्षा शुल्कों और विद्यालय शुल्कों के भुगतान के लिए गिरो मॉडेल पर आधारित एक इलेक्ट्रॉनिक बिल भुगतान प्रणाली विकसित किए जाने की आवश्यकता महसूस करती है।

प्रतिभूतिकरण बैंकों के लिए मंहगा हो सकता है

सरकार द्वारा इस वर्ष जून से निवेशकों पर लगाए जाने वाले एक अतिरिक्त कर के परिणामस्वरूप प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने हेतु निजी और विदेशी बैंकों को उपलब्ध एक मुख्य मार्ग उनके लिए मंहगा हो जाएगा। गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों, जो अपने ऋण संविभाग को इन बैंकों के पक्ष में प्रतिभूत करके निधियां जुटाती हैं, को उच्चतर ब्याज दर देनी पड़ सकती है, क्योंकि बैंक इस अतिरिक्त कर-भार को जारीकर्ता पर डालने का प्रयास करेंगे। यदि बैंक संपूर्ण कर-भार को जारीकर्ताओं पर डालना चाहते हों, तो उन्हें लगभग 270 आधार अंकों से अधिक की उच्चतर ब्याज दर पर निवेश करना होगा।

बाज़ारों पर मौद्रिक नीति का प्रभाव विषम

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि विकसित और एकीकृत वित्तीय बाज़ार मौद्रिक नीति के प्रभावों के प्रभावी और विश्वसनीय प्रेषण की पूर्वापेक्षाएं हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए एक अनुसंधान की रिपोर्ट का कहना है कि "मौद्रिक नीति का प्रेषण मांग मुद्रा दर में अच्छी तरह कार्य करता है, क्योंकि वह सुदृढ़ता के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभावित होता है। जहां तक वित्तीय बाज़ार के अन्य चरों (शेयर बाज़ार को छोड़कर) का सम्बन्ध है, उक्त अध्ययन में मौद्रिक नीति के आघातों से प्रेषण के प्रमाण मिले हैं।" भारतीय बैंकिंग प्रणाली में एक दशक से अधिक अवधि में कम से कम जनवरी तक

जमाराशियों में न्यूनतम वृद्धि दर्ज हुई है। वित्त वर्ष 2012 में बचत दरें वित्त वर्ष 08 के 37% के उच्च स्तर से घट कर सकल घरेलू उत्पाद की 31% रह गईं। भारत में वित्तीय बाज़ारों तक मौद्रिक नीति का प्रेषण विषम है - मौद्रिक प्रणाली के घाटे वाले मोड में होने पर यह विस्तारपरक चरण की अपेक्षा अधिक तीव्र और स्थिर रहती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यात अर्जनों को वापस लाने की अवधि घटाई

चालू खाते के बढ़ते घाटे की पृष्ठभूमि में देश में डालर आकर्षित करने के एक अभियान में भारतीय रिज़र्व बैंक ने निर्यातकों से बिक्री से प्राप्त राशियों की वसूली अवधि को निर्यात की तिथि से 12 माह से घटा कर तात्कालिक प्रभाव से 9 माह कर दिया है। निर्यातकों के लिए निर्यातित माल या सॉफ्टवेयर के पूर्ण मूल्य का निरूपण करने वाली रकम की वसूली और उसके भारत में प्रत्यावर्तन की बढ़ी हुई अवधि निर्यात की तिथि से 31 मार्च, 2013 तक उपलब्ध थी।

विनियामकों के कथन

नकदी की कमी से निपटने के लिए हम सभी विकल्पों का उपयोग करेंगे

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव ने चेतावनी दी है कि यह मान्यता कि खुले बाज़ार के परिचालन (OMOs) अधिमान्य साधन होंगे, गलत है। हम इस बात के अधार पर कि हम चलनिधि की स्थिति कैसी होनी चाहिए इसका किस प्रकार निर्धारण करते हैं, हमें उपलब्ध सभी विकल्पों का उपयोग करेंगे। यह खुले बाज़ार के परिचालन या आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) या कोई भी चीज़ हो सकती है।" अधिकांशत: सुस्त सरकारी व्ययों के कारण पैदा हुई निधि की अतिशय कमी से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने मार्च में समाप्त वित्त वर्ष 2012-13 में अपने खुले बाज़ार के परिचालनों के माध्यम से 1.3 लाख करोड़ रुपये के बॉण्ड खरीदे हैं। कई एक अर्थशास्त्रियों ने वर्तमान वित्त वर्ष में इंस संख्या के 1.5 -1.6 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगा रखा है।

अल्प-लागत वाले आवासों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार मार्ग दो वर्ष विस्तारित

कम्पनियों को प्रमुख मूलभूत सुविधा क्षेत्रों के लिए सस्ती निधिया प्राप्त करने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी उधार मानदंडों को सरल बना दिया है। भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री एच.आर. खान ने कहा है कि "भारतीय रिज़र्व बैंक ने वहनीय आवासों के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार में छूट, जो पहले एक वर्ष थी, को विस्तारित करके अब दो वर्ष कर दिया है और कुछेक अधिक महीनों क *छूट* अनुमत किया है।" हालांकि, 40 बिलियन अमरीकी डालर की बाह्य वाणिज्यिक उधार सीमा में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हुआ है, शीर्ष बैंक शीघ्र ही मूलभूत सुविधा कम्पनियों की एकसमान परिभाषा जारी करेगा। पिछले वर्ष दिसम्बर में भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्थावर

संपदा के विकासकर्ताओं और आवास वित्त कम्पनियों को अल्प-लागत वाली आवास परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए पिछले वित्त वर्ष में बाह्य वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से 1 बिलियन अमरीकी डालर तक जुटाने की अनुमति दी थी। बाह्य वाणिज्यिक उधारों के माध्यम से जुटाई गई निधियां अल्प-लागत वाली आवास परियोजनाओं का विकास करने अथवा व्यक्तियों को 30 लाख रुपये अथवा उससे कम कीमत वाली इकाइयां खरीदने हेतु 25 लाख रुपये तक के ऋण प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

मुद्रास्फीति नियंत्रित करने में राज्यों की भूमिका महत्वपूर्ण

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. डी. सुब्बाराव के अनुसार राज्यों और केन्द्र के ऋण निर्गमन उधार के बढ़े हुए आकार, मुद्रास्फीति जोखिम, बैंकों के अतिशय सरकारी प्रतिभूतिया रखने और वर्ष के बाद वाले भाग में निजी ऋण की मांग में अपेक्षित वृद्धि के कारण एक चुनौती सिद्ध होंगे। गवर्नर ने यह राय व्यक्त की है कि मुद्रस्फीति के प्रबन्धन में राज्यों को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, क्योंकि वे अर्थव्यवस्था में आपूर्ति सम्बन्धी बाधा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण हितधारक हैं। आपूर्ति से सम्बन्धित बाधा का निवारण वे कृषि मे उत्पादकता बढ़ा कर, मूलभूत सुविधा, विशेषत: ग्रामीण मूलभूत सुविधा में सुधार ला कर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को युक्तियुक्त बना कर तथा निवेश के लिए समर्थकारी वातावरण सृजित करके अभिशासन से सम्बन्धित चिंताओं का निराकरण करके कर सकते हैं। डॉ. सुब्बाराव ने वित्तीय समावेशन, चिट फण्डों, पोंजी योजनाओं तथा बहु-स्तरीय विपणन योजनाओं से सम्बन्धित मामलों में बुनियादी स्तर पर बढ़ी हुई चौकसी के लिए राज्य सरकारों और समस्त हितधारकों के बीच समन्वय पर भी बल दिया है।

बीमा

जीवन बीमाकर्ताओं की प्रीमियम वृद्धि को वित्त वर्ष 14 में चुनौती का सामना करना पड़ेगा

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) के आंकड़ों के अनुसार अर्थव्यवस्था में व्याप्त मंदी तथा परंपरागत उत्पाद मानदंडों में परिवर्तन के कारण चालू वित्त वर्ष के जीवन बीमाकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण होने की आशा है। जीवन बीमा क्षेत्र में वित्त वर्ष 2012-13 के लिए नये व्यवसाय के

प्रीमियमों में 6.3% की गिरावट दर्ज हुई। जीवन बीमा में 31 मार्च, 2013 को समाप्त वर्ष के लिए पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में संग्रहीत 1,14,232.72 करोड़ रुपये के मुकाबले 1,07, 010.68 करोड़ रुपये के नये प्रीमियम एकत्रित किए गए। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDA) ने हाल ही में पारंपरिक उत्पाद ढाचे के सम्बन्ध में नये दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनमें यह अपेक्षित है कि जीवन बीमाकर्ताओं के लगभग 70-75 % उत्पाद पोर्टफोलियो को विनियमनों के अनुरूप बनाने हेतु पुन: सृजित किया जाए।

अर्थव्यवस्था

चालू खाते का घाटा इस वर्ष 5% से कम रहेगा

मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. रघुराम जी. राजन ने कहा है कि वर्ष 2012-13 की 4थी तिमाही (जनवरी-मार्च) में केन्द्र का चालू खाते का घाटा सोने और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से सहायता पा कर सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के 4% से कम रहेगा। उन्होंने कहा कि 2013-14 में चालू खाते के घाटे के 5% रहने की संभावना है। पहले यह इस वर्ष 5% से कम के स्तर पर आएगा। अगले वर्ष में हमें इसे 4% से कम के स्तर पर और आगामी वर्षों में उससे भी कमतर स्तर पर लाना है। वर्ष 2012-13 की 3री तिमाही के दौरान चालू खाते का घाटा अब तक के सबसे निचले स्तर 6.7 % पर पहुंच गया था। वर्ष के पहले नौ महीनों मे यह 5.4% या 71.7 बिलियन अमरीकी डालर था।

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 14 की वृद्धि का पूर्वानुमान घटा कर 6.1% किया

अपने अद्यतन भारत विकास अद्यतन में विश्व बैंक ने वर्तमान वित्त वर्ष हेतु भारत के लिए अपने वृद्धि पूर्वानुमान को 7% से घटा कर 6.1% कर दिया है। उक्त अद्यतन में कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्थथा में वृद्धि की गति पुन: आ रही है तथा इस वृद्धि में दीर्घकालिक दृष्टि से उच्च पुनरुत्थान की संभाव्यता क्रमिक रूप से आने की आशा है। यद्यपि वित्त वर्ष 2013 में चालू खाते का घाटा रिकार्ड के रूप में उच्च था, मध्य अवधि में उसके कम होने की संभावना है। विश्व बैंक ने यह भी कहा है कि यद्यपि राजकोषीय घाटे में कमी आई है, राजकोषीय उपज सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में ऋण को घटाने में अधिकाधिक रूप से महत्वपूर्ण होती है।

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
भारतीय स्टेट बैंक	इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया	समझौता ापन कोरिताई कम्पनियों की भारतीय स्टेट बैंक से उनकी वित्तीय आवश्यकताएं परी करने में सहायता करेगा।

	ऑफ इंडिया	उनकी वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने में सहायता करेगा।
	हार्वेल अगुवा इंडिया प्रा. लि.	राष्ट्रीय स्तर के गठजोड़ में शामिल तथा स्वयं अपने उत्पादन एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों , फसल प्रबन्धन सेवाओं तथा ग्रीन हाउसेज (संरक्षित खेती) के विनिर्माण एवं बिक्री में संलग्न।
	स्पैनिश बैंक बैंको बिलबाओ विजकाया	

	अर्जेन्टीना, एस.ए. (बीबी वीए)	लातीनी अमेरिका और स्पेन में व्यवसाय परिचालन का विकास करने हेतु।
करूर वैश्या बैंक	लुलू इंटेरनेशनल एक्सचेंज , अबू धाबी और ओसीसी एक्सचेंज हाउस, दुबई	गति प्रेषण व्यवस्था के तहत प्राप्त राशियां हिताधिकारियों के खातों में उसी दिन इलेक्ट्रॉनिक विधि से जमा की जाएंगी।
फेडरल बैंक	टाटा कन्सल्टैंसी सर्विसेज	पासपोर्ट सेवा केनद्रों में एटीएम स्थापित करने के लिए।
हांगकांग स्थित इंडस्ट्रियल एण्ड कॉमर्शियल बैंक ऑफ चाइना	इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एण्ड फाइनैन्सियल सर्विसेज	सम्बन्धित वित्तीय सेवाओं, व्यापार, कारपोरेट बैंकिंग, निवेश बैंकिंग और खजाने से सम्बन्धित सेवाओं, ऋण संग्रहण ऐसी परियोजनाओं के लिए परामर्शी और उक्त ा, क्षेत्र में अनुमेय अन्य रूपों वाले आर्थिक सहयोग की सहित मूलभूत सुविधा परियोजना विकास सेवाएं प्रदान करने हेतु।

नयी नियुक्तियां

नाम	पदनाम / संगठन
डॉ. सदक्कदुल्ला	तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक (आरडी)
डॉ. नचिकेत एम. मोर	भारतीय रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड में निदेशक

ग्रामीण बैंकिंग

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को ग्रामीण पहल को अगले वर्ष तक ले जाने की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि जिन बैंकों ने वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने का लक्ष्य पार कर लिया है, उन्हें अतिरिक्त संख्या को अगले वित्त वर्ष तक आगे ले जाने की अनुमति होगी। मौजूदा शाखा विस्तार मानदंडों के अनुसार बैंकों को नयी शाखाओं के 25% बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में खोलना है। जिन बैंकों ने 25% के वार्षिक लक्ष्य को पार कर लिया है, उन्हें शाखाओं की अतिरिक्त संख्या को अगली द्विवर्षीय योजना तक आगे ले जाने की अनुमति होगी। बैंकों को बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में

शाखाएं खोलने के कार्य को वित्तीय समावेशन योजना के साथ तीन-वर्षीय चक्र सह- सीमा (co-trminus) तक आगे ले जाने की सलाह दी गई है।

जून, 2013 माह के लिए लागू होने वाली विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमाराशियों लिबोर / अदला-बदली दरें

विदेशी मुद्रा अनिवासी बैंक के लिए लिबोर / अदला-बदली					
	लिबोर	अदला-बदली			
मुद्रा	1 वर्ष	2 वर्ष	3 वर्ष	4 वर्ष	5 वर्ष
अमरीकी डालर	0.68920	0.448	0.636	0.898	1.161
जीबीपी	0.88313	0.6795.	0.7840	0.9620	1.1473
यूरो	0.39071	0.430	0.574	0. 740	0.925
जापानी येन	0.43643	0.290	0.360	0.433	0.543
कनाडाई डालर	1.78650	1.432	1.551	1.704	1.854
आस्ट्रेलियाई डालर	3.33800	2.740	2.930	3.160	3.320
स्विस फ्रैंक	0.24550	0.150	0.235	0.368	0.520
डैनिश क्रोन	0.49600	0.5960	0.7300	0.9080	1.0960
न्यूजीलैंड डालर	2.77000	2.985	3.185	3.360	3.525
स्वीडिश क्रोन	1.20750	1.312	1.462	1.613	1.773
सिंगापुर डालर	0.47000	0.560	0.745	0.965	1.180
हांगकांग डालर	0.46000	0.560	0.730	0.890	1.130
एमवाईआर	3.24000	3.250	3.320	3.390	3.490

स्रोत : भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियां

मद	24 मार्च, 2013 के दिन	24 मार्च, 2013 के दिन

	बिलियन् रुपये	मिलियन अमरीकी डालर
	1	2
कुल प्रारक्षित निधियां	16, 208, 3	2 92,076 1
क) विदेशी मुद्रा आस्तियां	14, 545.0	261,565. 8
ख) सोना	1, 297, 9	23, 974. 1
ग) विशेष आहरण अधिकार	240, 0	4, 316.5
घ) अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	123.4	2, 219.7

13

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

प्रारक्षित निधियां बढ़ाने के लिए भारती रिज़र्व बैंक द्वारा डालर की खरीद

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा की अपनी घटती प्रारक्षित निधियों को बढ़ाने के लिए डालरों की खरीद शुरू कर दी है, क्योंकि विदेशी निवेशकों द्वारा उच्चतर प्रतिलाभ प्रा्त करने हेतु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध कराए जाने के कारण उसने (मार्च में) 28 महीनों में पहली बार बाज़ार से अमरीकी डालर खरीदा है । भारतीय रिज़र्व बैंक, जिसने यह घोषित किया था कि वह मुद्रा स्तर को बनाए रखने के लिए मुद्रा बाज़ार में हस्तक्षेप नहीं करेगा, ने मार्च में 830 मिलियन अमरीकी डालर खरीदा। उसने वायदा बाज़ार से भी डालरों की खरीद की, क्योकि बकाया वायदा बिक्री एक माह पहले के 12 बिलियन अमरीकी डालर से घट कर मार्च में 11 बिलियन अमरीकी डालर हो गई।

वित्तीय समावेशन

कारबार संपर्कियों ने दो लाख से अधिक गावों तक बैंकिंग पहुंचाई

2.11 लाख से अधिक गांवों, जिनमें तीन वर्ष पहले तक बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं थीं, को अब 1.52 लाख कारबार संपर्कियों द्वारा सेवा प्रदान की जा रही है। भारतीय रिज़र्व बैंक की कार्यपालक निदेशक डॉ. दीपाली पंत जोशी ने कहा है कि वित्तीय समावेशन योजना (FIP) 2010-13 , जो विविध बैंकों द्वारा अप्रैल, 2010 में प्रारंभ की गई थी, ने अब तक 2.11 लाख गांवों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान की हैं। इसके पूर्व बैंकिंग सुविधा सम्पन्न गांवों की संख्या 67,694 थी। कारबार संपर्कियों की संख्या, जो वित्तीय समावेशन योजना कार्यान्वित किए जाने के पूर्व 34,532 थी, दिसम्बर, 2012 के अंत में बढ़ कर 152 लाख तक पहुंच गई और विविध बैंकों ने 5,694 ग्रामीण शाखाएं खोलीं।

ग्रामीण भारत में साहूकारों का प्रभुत्व

भारतीय रिज़र्व बैंक के दस्तावेज़ के अनुसार वर्ष 2000 में गैर-संस्थागत ऋण खेतिहरों के कुल ऋण का 39% था, जिसमें से साहूकारों की हिस्सेदारी 27% थी। यद्यपि साहूकारों का अंश 1951 के 70% के शिखर से कम हो गया है, 1981 के बाद उनके उधारों में पुनरुत्थान परिलक्षित हुआ था। 1991 से 2002 तक किसानों को ऋणों में पेशेवर साहूकारों का हिस्सा दोगुना बढ़ कर 20% हो गया और वाणिज्यिक बैंकों का 30% से घट कर 24% रह गया। ऋण के अनौपचारिक स्रोतों में वृद्धि का मुख्य कारण वह आसानी रही है जिस पर ऋण लिये जा सकते हैं और नियमित चुकौती का अभाव । यह आसान पहुंच किसानों को बाद वाले स्रोत के उच्चतर ब्याज दरें प्रभारित करने के बावजूद साहूकारों के पास जाने हेतु प्रेरित करती है।

14

सूक्ष्मवित्त

25 लाख महिला स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दरों पर ऋण मिलेगा

महिला सशक्तीकरण के माध्यम से गांवों से गरीबी को पूर्णत: मिटाने के लिए प्रारंभ किए गए केन्द्रीय सरकार के एक कार्यक्रम के तहत 25 लाख से अधिक महिला स्वयं सहायता समूहों को कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान किया जाएगा। वित्त मंत्री श्री पी. चिदम्बरम द्वारा 2013-14 के बजट में की गई घोषणा के अनुसरण में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) के अधीन कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक के ऋण प्राप्त करने में समर्थ बनाते हुए ब्याजगत सरकारी अनुदान के प्रावधान को अनुमोदित कर दिया है। समय पर ऋण चुकौती करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह को 3% की अतिरिक्त छूट मिलेगी।

अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (क्रमश :)

दबाव-परीक्षण पर चर्चा को जारी रखते हुए हम छठे और सातवें सिद्धांत को समझेंगे।

6. बैंक को अपने दबाव-परि3न ढांचे को नियमित रुप से बनाए और अद्यतन रखना चाहिए. दबाव-परीक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता और उसके साथ ही महत्वपूर्ण संघटकों की सुदृढ़ता का नियमित एवं स्वतत्र रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

निर्णयों के महत्व और विचार किए गए आघातों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए दबाव-परीक्षणों की प्रभावशीलता और सुदृढ़ता का गुणात्मक और उसके साथ ही मात्रात्मक रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन के क्षेत्रों में निम्नलिखित का समावेश होना चाहिए :

- कार्यक्रम के उद्देश्यों को पूरा करने की दृष्टि से उसकी प्रभावशीलता
- प्रलेखीकरण
- विकासपरक कार्य
- प्रणाली कार्यान्वयन

- प्रबन्धन की अन्तर्दृष्टि
- डाटा की गुणवत्ता और
- प्रयुक्त मान्यताएं

गुणात्मक प्रक्रियाओं में बैंक के भीतर और उसके बाहर अन्य परीक्षणों के साथ निर्देश चिन्हों का समावेश होना चाहिए। चूंकि दबाव-परीक्षण के विकास और अनुरक्षण की प्रक्रियाओं में प्राय: निर्णयात्मक एवं विशेषज्ञ निर्णय (परीक्षित की जाने वाली मान्यताओं, दबाव के अंशाकन आदि) अन्तर्निहित होते हैं जोखिम प्रबन्धन और आंतरिक लेखा-परीक्षा जैसे स्वतंत्र नियंत्रण के कार्यों को भी इस प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए।

7. दबाव-परीक्षण की कार्यप्रणाली और परिदृश्य चयन दबाव-परीक्षण में फर्म-व्यापी स्तर सहित कई प्रकार के जोखिमों एवं व्यवसाय क्षेत्रों का समावेश होना चाहिए। बैंक को फर्म-व्यापी जोखिम की सम्पूर्ण स्थिति का पता लगने के लिए उसके सभी प्रकार के दबाव-परीक्षण क्रिया-कलापों को एक सार्थक विधि से एकीकृत करने में समर्थ होना चाहिए।

किसी दबाव-परीक्षण कार्यक्रम में स्थिर एवं व्यापक रूप से उत्पाद - व्यवसाय और कम्पनी विशिष्ट विचारों का समावेश होना चाहिए। दबाव-परीक्षण के उद्देश्य के अनुकूल दानेदारी वाले स्तर का उपयोग करते हुए दबाव-परीक्षण के कार्यक्रमों को समस्त सम्बन्धित जोखिम कारकों पर उनके बीच विद्यमान अंतर-सम्बन्धों को ध्यान में रखते हुए उन पर आघातों के प्रभाव की जांच करनी चाहिए। बैंक को दबाव-परीक्षणों का उपयोग जोखिम संकेन्द्रणों की पहचान करने, उन पर निगरानी रखने और उनका नियंत्रण करने हेतु भी करना चाहिए।

जोखिम संकेन्द्रणों से उपयुक्त रूप से निपटने के लिए परिदृश्य फर्म-व्यापी और व्यापक होने चाहिए जिनमें तुलनपत्र में शामिल और तुलनपत्र-बाह्य आस्तियों, उनके संविदात्मक स्वरूप से अलग आकस्मिक एवं अनाकस्मिक जोखिमों का समावेश होना चाहिए। इसके अलावा, दबाव-परीक्षणों को बाज़ार की उन स्थितियों में संभाव्य परिवर्तनों की पहचान और निराकरण करना चाहिए जो जोखिम संकेन्द्रणौं के प्रति बैंक की अनाश्रयताओं (Exposures) को प्रभावित कर सकते हैं। दबाव-परीक्षणों के प्रभाव का मूल्यांकन आम तौर पर एक या उससे अधिक मापों के समक्ष किया जाता है। प्रयुक्त विशिष्ट माप दबाव-परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्य, विश्लेषित किए जा रहे जोखिमों और पोर्टफोलियो तथा परीक्षण के अधीन विशिष्ट मुद्दे पर निर्भर करेंगे। प्रभाव का पर्याप्त असर संप्रेषित करने के लिए कई प्रकार के मापों का उपयोग किया जाना चाहिए।

प्रयुक्त होने वाले विशिष्ट माप हैं :

- आस्ति के मूल्य;
- लाभ एवं हानि का लेखांकन;
- आर्थिक लाभ एवं हानि;
- विनियामक पूंजी या जोखिम-भारित आस्तियां;
- किफायती पूंजी की आवश्यकताएं ; और

- चलनिधि एवं निधीयन अंतर

फर्म-व्यापी आधार पर सुसंगत दबाव-परीक्षण परिदृश्यों का विकास करना एक कठिन कार्य है, क्योंकि विभिन्न पोर्टफोलियो के लिए जोखिम कारक व्यापक रूप से भिन्न होते है तथा उनके संस्तर अलग-अलग होते हैं। उदाहरण के लिए बाज़ार और ऋण जोखिम के लिए कोई संगत परिदृश्य प्राप्त करना उतना आसान नही होता, क्योंकि बाज़ार जोखिम शीघ्रतापूर्वक उद्भूत होता है, जबकि ऋण जोखिम को पूरी प्रणाली में व्याप्त होने के लिए अपेक्षाकृत लम्बे समय-संस्तर की जरूरत होती है। हालांकि, व्यवसाय मॉडेल को प्रभावी रूप से चुनौती देने तथा निर्णयन प्रक्रिया को समर्थन प्रदान करने के लिए परिदृश्यों में सभी पोर्टफोलियों और सभी समयों से जुड़े जोखिमों के स्वरूप का मूल्यांकन किया

जाना चाहिए। इससे सम्बन्धित एक प्रासंगिक पहलू है किसी दबाव-परीक्षण के अंतिम प्रभाव का निर्धारण करने हेतु चलनिधि की स्थितियां।

वित्तीय क्षेत्र की मूलभूत जानकारी

"इन्कोटर्म्स" की परिभाषा

अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्य संघ द्वारा प्रकाशित व्यापार की वे शर्तें जिनका प्रयोग सामान्यतया अन्तरराष्ट्रीय और घरेलू, दोनों ही संविदाओं में किया जाता है। "अन्तरराष्ट्रीय वाणिज्यिक शर्तों" के संक्षिप्त रूप इन्कोटर्म्स का उपयोग विभिन्न देशों में व्यापारियों की एक-दूसरे को समझने में सहायता करके अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाने हेतु किया जाता है। "इन्कोटर्म्स" का सर्वप्रथम विकास 1936 में किया गया था तथा वे व्यापार की वर्तमान प्रथाओं के अनुरूप बनाए जाने के उद्देश्य से समय-समय पर अद्यतन की जाती रहती रहती हैं। इन अद्यतनों के कारण संविदाओं में यह विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि उनमें इन्कोटर्म्स के किस संस्करण का उपयोग किया जा रहा है- यथा- इन्कोटर्म्स 2000)।

शब्दावली

कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था

कम्पनी ऋण पुनर्व्यवस्था से अभिप्राय है किसी कम्पनी के/की बकाया दायित्व / बाध्यता की पुनर्व्यवस्था, जो प्राय: कम्पनी पर कर्ज के बोझ (भार) को भुगतान की जाने वाली रकम को घटा कर और कम्पनी को जितने समय में अपनी बाध्यता को वापस चुकाना है, उसे बढ़ा कर प्राप्त की जाती है। यह किसी कम्पनी को बाध्यताओं / दायित्व को पूरा करने में अपने सामर्थ्य को बढ़ाने की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा, लेनदारों द्वारा कम्पनी में इक्विटी की स्थिति के बदले कुछेक कर्ज माफ किए जा सकते हैं।

संस्थान की गतिविधियां

जून, 2013 माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा

क्रम सं.	कार्यक्रम	दिनांक
1	विपणन एवं ग्राहक सेवा पर 3रा कार्यक्रम	3 से 7 जून, 2013 तक
2	व्यापार वित्त पर 2रा कार्यक्रम	10 से 14 जून, 2013 तक
3	टॉपसिम तुलनपत्र अनुरूपण	17 से 18 जून, 2013 तक
4.	8वां लीडरशिप कार्यक्रम - पीडीआई 9वां हाउस	17 से 19 जून, 2013 तक

17

मई, 2013 माह के दौरान पूरी की गई प्रशिक्षण गतिविधियां

क्रम सं.	कार्यक्रम	तिथि
1.	5वां ऋण मूल्यांकन (औद्योगिक एवं वाणिज्यिक अग्रिम)	6 से 10 मई, 2013 तक
2	आवास वित्त पर 2रा कार्यक्रम	13 से 15 मई 2013 तक
3	लघु एवं मध्यम उद्यम वित्तीयन पर 4था कार्यक्रम	27 से 31 मई , 2013 तक

संस्थान समाचार

"ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक" पर संगोष्ठी

- संस्थान ने 10 जून, 2013 को इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, गुवाहाटी में भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) के सहयोग से "ग्राहक सेवा और बैंकिंग संहिता एवं मानक " पर 8वीं संगोष्ठी का आयोजन किया था। मुख्य व्याख्यान भारतीय बैंकिंग संहिता और मानक बोर्ड (BCSBI) के अध्यक्ष श्री ए.सी. महाजन द्वारा दिया गया और समापन व्याख्यान भारतीय रिज़र्व बैंक, क्षेत्रीय निदेशक श्री पी. के. जेना द्वारा दिया गया। उक्त संगोष्ठी में 76 सहभागियों ने भाग लिया।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : 69228 / 98 के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / दक्षिण -42 / 2010 -12
* प्रत्येक महीने की 25वीं को प्रकाशित * मुंबई पत्रिका चैनल छंटाई कार्यालय मुंबई - 1 पर प्रेषित
* प्रेषण की तिथि प्रत्येक महीने की 25वीं से 30वीं तारीख

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपने पोर्टल पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

ई-मेल के माध्यम से आईआईबीएफ विजन

संस्थान ने आईआईबीएफ - विज़न उसके पास पंजीकृत ई-मेल पतों पर ई-मेल द्वारा भेजना आरंभ कर दिया है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल पते संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करा रखे हैं, उनसे

अनुरोध है कि वे अपने ई-मेल पते यथाशीघ्र पंजीकृत करा लें। आईआईबीएफ - विज़न संस्थान के पोर्टल में डाउनलोड करने हेतु भी उपलब्ध है।

बाज़ार की खबरें

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

90
85
80
75
70
65
60
55
50
02/05/13 03/05/13 08/05/13 10/05/13 13/05/13 14/05/13 20/05/13 22/05/13
23/05/13 28/05/13 29/0513
अमरीकी डालर यूरो 100 जापानी येन पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

- 2री को रुपये में 14 पैसे की गिरावट आई और वह प्रति डालर 54.82 पर बंद हुआ।
- 13वीं को रुपया अमरीकी डालर के 55 वाले मनोवैज्ञानिक चिन्ह, एक एसा स्तर जो 8 जनवरी से देखने में नहीं आया था, को पार कर गया, क्योंकि धीमी निर्यात वृद्धि की पृष्ठभूमि में सोने और तेल की बढ़ती मांग को देखते हुए अमरीकी मुद्रा की मांग बढ़ती लगी। किन्तु वह पुन: बढ़ कर 10वीं के 54.80 के स्तर से उच्चतर स्तर 54.74 पर बंद हुआ।
- 20वीं को भारतीय रुपया लुढ़क कर साढ़े पांच माह के न्यून स्तर पर पहुंच कर अमरीकी डालर के समक्ष 55.11 से कम पर बंद हुआ, क्योंकि निवेशकों पर स्टैंडर्ड एण्ड पुअर के श्रेणी में गिरावट का खतरा मंडराने लगा तथा तेल आयातकों

से अमरीकी मुद्रा की मांग सुदृढ़ बनी रही।

- 21वीं को भारतीय रुपया पिछले बंद वाले स्तर से 0.5% लुढ़क कर प्रति डालर 55.41 हो गया, जो पिछले नवम्बर में परिलक्षित स्तरों के समकक्ष था। इस भय के बीच कि इस सप्ताह फेडरल रिज़र्व के अध्यक्ष श्री बेन बेमांके द्वारा अमरीकी अर्थव्यवस्था में सुधार की शुरुआत के कारण सहज मौद्रिक नीति को समाप्त करने का संकेत दिए जाने पर पूंजी प्रवाह में सुस्ती आ सकती है, अमरीकी डालर के समक्ष भारतीय रुपया लुढ़क कर छ: माह के न्यून स्तर पर आ गया।
- सभी महत्वपूर्ण मुद्राओं के समक्ष रुपये में सभी स्तरों पर मूल्यह्रास हुआ।

भारित औसत मांग दरें

7.6
7.5

7.4
7.3
7.2
7.1
7
6.9
6.8
6.7
6.6

02/05/13 03/05/13 04/05/13 06/05/13 11/05/13 13/05/13 18/05/13 20/05/13 23/05/13 24/05/13

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मार्च, 2012

- माह की शुरूआत में मांग दरें 7.55% पर स्थिर रहीं और माह के अंत में 7.3% पर बंद हुईं।
- चलनिधि में सुधार के फलस्वरूप 4थी, 11वीं और 18वीं को दरें 7% पर स्थिर रहीं।
- कुल मिला कर दरं श्रेणीबद्ध रहीं।

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

20400
20200
20000
19800
19600
19400
19200

02/05/13 03/05/13 07/05/13 09/05/13 10/05/13 13/05/13 17/05/13 20/05/13 22/05/13

23/05/13 27/05/13 28/05/13 29/05/13

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

डॉ. आर. भास्करन द्वारा मुद्रित, डॉ. आर. भास्करन द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , 6 - बी मोहता भवन, 3री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - 400 018 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई -400 070 से प्रकाशित।

संपादक : डॉ. आर. भास्करन

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्सियल- II, टॉवर -1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22 2503 9604 / 9607 फैक्स : 91-22-2503 7332
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom5 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जून, 2013